

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

11 नवंबर, 2019

“मूडीज़ ने ज्ञात जोखिमों को चिह्नित करते हुए दर्शाया है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधारों के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।”

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत को झटका देते हुए उसके क्रेडिट रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। मूडीज़ इंडिया की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की तुलना में एक पायदान अधिक है। फिर भी, आउटलुक रिवीजन को देखा जाना चाहिए कि यह क्या दर्शाता है क्योंकि यह एक चेतावनी है कि यदि अर्थव्यवस्था जल्द ही वापस पटरी पर नहीं आती है तो यह रेटिंग और भी प्रतिकूल हो जाएगी।

मूडीज़ द्वारा जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें से कोई भी अज्ञात नहीं है। विकास में मंदी और राजकोषीय घाटे तथा उधार पर इसके प्रभाव प्रमुख चिंताएँ हैं। जहाँ एक तरफ तीसरी तिमाही में जारी मंदी के साथ कर राजस्व वृद्धि बजट के अनुमान के हिसाब से बहुत दूर है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर राजस्व व्यापक अंतर से कम हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ, सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अधिक खर्च करने के लिए मजबूर हो गयी है।

पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च को आगे बढ़ाने के अलावा, सरकार ने पिछले महीने 1.45 लाख करोड़ की कॉरपोरेट कर में रियायतें दी थीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1.76 लाख करोड़ लाभांश का भुगतान देने के कारण, बजट अंकगणित आशावादी है और अब यह निश्चित है कि सरकार जीडीपी के 3.3% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य के अभाव का सामना करेगी।

मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि यह घाटा जीडीपी के 3.7% तक चला जाएगा। रेटिंग एजेंसियां राजकोषीय घाटे के प्रति अति-संवेदनशील हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि भारत की उधारी लगभग पूरी तरह से घरेलू है। जीडीपी के लिए बाहरी ऋण सिर्फ 20% है लेकिन हालिया रेटिंग निवेशक की भावना पर जरूर प्रभाव डालेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक मजबूत बने हुये हैं और सरकार की ओर से किए गए उपायों से निवेश में तेजी आएगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘मूडीज़ द्वारा रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बदलकर नकारात्मक करना इस जोखिम को दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि पहले की तुलना में कम रह सकती है।’

यह आंशिक रूप से लंबे समय से चली आ रही आर्थिक एवं संस्थागत कमजोरी को दूर करने में सरकार की प्रभावी नीति में कमी को दर्शाता है। इन कमजोरियों का मूडीज़ ने पहले ही अनुमान जताया था। इनकी वजह से देश का कर्ज धीरे-धीरे बढ़ेगा, जो कि पहले से ही उच्च स्तर पर है।

यहाँ समस्या यह है कि मूडीज़ की रेटिंग उस वक्त आई है जब अर्थव्यवस्था में हल्का सुधार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल्स और व्हाइट गुड्स (बड़े पैमाने पर बिजली के सामान, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन आदि) की

बिक्री अच्छी खबर है।

बेशक, इसकी संभावना है कि इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बड़े डिस्काउंट दिए गये होंगे, लेकिन दूसरे सकारात्मक संकेत भी हैं जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए, RBI द्वारा लगातार दूसरे पखवाड़े के लिए जारी किए गए बैंक क्रेडिट में वृद्धि।

सरकार को नए सुधारों पर और जीएसटी में व्याप्त खामियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि राजकोषीय घाटे में कमी को समाहित किया जाना है तो बजट में अपने लिए निर्धारित 1.05 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को व्यापक अंतर द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पिछले दो महीनों में घोषित सहायक उपायों के क्रियान्वयन को बारीकी से देखा जाना चाहिए।

GS World टीम...

मूडीज ने भारत की रेटिंग 'स्थिर' से घटाकर 'नकारात्मक' की

संदर्भ

- चर्चित अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग 'स्थिर' से घटाकर 'नकारात्मक' कर दी है। उसका कहना है कि देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार अभी धीमी ही रहेगी।
- इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के दौरान में भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ पांच फीसदी की दर से बढ़ी।
- यह 2013 के बाद इसका सबसे बुरा प्रदर्शन है। जानकारों के मुताबिक उपभोक्ता मांग घटने के साथ-साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में कमी और वैश्विक कारणों के चलते भी ऐसा हो रहा है।
- मूडीज ने विदेशी मुद्रा रेटिंग के बीएए-2 को बरकारर रखा, लेकिन मार्च, 2020 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में 3.7 फीसदी राजकोषीय घाटे रहने का अनुमान जाहिर किया।
- वहीं सरकार का अनुमान 3.3 फीसदी राजकोषीय घाटे का है। माना जा रहा है कि सुस्त विकास दर और कॉरपोरेट कर में कटौती के चलते राजस्व घटने से राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार को झटका लग सकता है।

मुख्य बिंदु

- भारत का क्रेडिट रेटिंग आउटलुक नकारात्मक किया, जो साख को घटाने की दिशा में पहला कदम है।
- आगे विकास दर नीचे रहने का बढ़ गया है जोखिम।
- सरकारी खजाने पर बढ़ा कर्ज, जो पहले से ही ज्यादा था।
- सरकार के प्रयासों से तात्कालिक सुस्ती कम होनी चाहिए, लेकिन बड़ी मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

क्या है मूडीज?

- मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है, जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। ये कंपनी बनी थी साल 1909 में, जिसे बनाया था जॉन मूडी ने। इस कंपनी को बनाने के पीछे जॉन मूडी का मकसद था स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग बताना। मतलब ये बताना कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बॉन्ड खरीदने पर ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके लिए जॉन मूडी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग किया करते थे। साल 1962 में अमेरिका की ही एक और कंपनी डॉन एंड ब्रॉडस्ट्रीट ने इसे खरीद लिया और विलय कर लिया। साल 2000 में डॉन एंड ब्रॉडस्ट्रीट ने मूडीज को अलग से एक कंपनी के तौर पर स्थापित कर दिया और इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया। फिर 2007 में मूडीज के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा बना मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसका काम था रेटिंग देना। दूसरा

हिस्सा था मूडीज एनालिटिक्स का, जिसके जिम्मे कंपनी के बचे हुए काम आ गए।

- मूडीज दुनिया के 135 देशों की क्रेडिट रेटिंग करती है। इसमें दो तरह की रेटिंग होती है- एक है क्रेडिट रेटिंग और दूसरा है आउटलुक रेटिंग।

कैसे काम करता है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस?

- मूडीज इन्वेस्टर सर्विस बॉन्ड मार्केट में लगे सरकार के पैसे और कारोबारियों के पैसे के आधार पर किसी देश के कर्ज लेने और उसे चुकाने की क्षमता की रेटिंग जारी करता है। अगर रेटिंग अच्छी आती है तो दुनिया भर के निवेशक उस देश में इन्वेस्ट करते हैं और अगर रेटिंग खराब आती है तो निवेशक उस देश में निवेश करने से कतराते हैं। फिलहाल, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस दुनिया के 135 देशों की क्रेडिट रेटिंग जारी करता है। इसके अलावा इसके जिम्मे और भी कई कॉर्पोरेट यूसर्स और उधार पैसे देने वाली संस्थाएं हैं। 44 देशों में कुल 13,700 लोग मूडीज के लिए काम करते हैं, जिनसे मिले डेटा का एनालिसिस करके यह कंपनी किसी देश की क्रेडिट रेटिंग जारी करती है।

कैसे होती है रेटिंग और क्या हैं उस रेटिंग के मायने?

- मूडीज की रेटिंग Aaa से लेकर C तक होती है। Aaa का मतलब होता है कि उस देश में निवेश की स्थितियां सबसे बेहतर हैं, वहीं C का मतलब है कि उस देश में निवेश की स्थितियां बेहद खराब हैं।
- **Aaa** : ये मूडीज की सबसे अच्छी रैंकिंग है। मतलब यह है कि कम वक्त के लिए लिया गया कर्ज आराम से चुकाया जा सकता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं।
- **Aa1 से Aa3 (Aa1, Aa2, Aa3)** : Aa1 से लेकर Aa3 तक की रेटिंग दूसरी सबसे अच्छी रेटिंग है। इसमें कर्ज न चुकाने की आशंका बेहद कम होती है यानी कि कम वक्त के लिए लिया गया कर्ज आराम से चुकाया जा सकता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं।
- **A1- A3 (A1, A2, A3)** : इसके तहत किसी देश की रेटिंग को अपर मीडियम माना जाता है। कर्ज चुकाने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। चीन इसी लिस्ट में शामिल है।

- चीन A1-A3 वाली श्रेणी में है, जबकि भारत उससे नीचे Baa1 से Baa3 वाली श्रेणी में है।
- **Baa1-Baa3 (Baa1, Baa2, Baa3)** : ये रेटिंग मीडियम होती है। इसमें कर्ज चुकाने में मामूली रिस्क हो सकता है। छोटे वक्त के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने की अच्छी क्षमता होती है और कर्ज न चुकाने या कुछ देर होने के लिए वाजिब वजहें होती हैं। अपना देश इसी श्रेणी में है।
- **Ba1-Ba3 (Ba1, Ba2, Ba3)** : इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले देश को लोन चुकाने में थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। इस लिस्ट में हंगरी शामिल है।
- **B1-B3 (B1, B2, B3)** : इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले देश लोन चुकाने में रिस्की हो सकते हैं। मतलब ऐसे देशों को लोन देने में खतरा हो सकता है। इथोपिया और ग्रीस इस लिस्ट में हैं।
- **Caa1-Caa3 (Caa1, Caa2, Caa3)** : इस क्रेडिट रेटिंग वाले देशों की स्थिति खराब होती है। इन्हें लोन देना और फिर उसे वापस हासिल करना बेहद रिस्की होती है। क्यूबा इस लिस्ट में शामिल है।
- **Ca** : इस क्रेडिट रेटिंग वाले देश डिफॉल्ट होने के करीब होते हैं। इन्हें दिए लोन को वापस मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है। बहुत मामूली गुंजाइश होती है कि ये देश मूलधन और ब्याज चुका सकते हैं। फिलहाल, इस लिस्ट में कोई भी देश नहीं है।
- **C** : यह किसी देश की सबसे खराब क्रेडिट रेटिंग है। इसका मतलब है कि वो देश डिफॉल्ट हो चुका है। उसे दिए गए पैसे में ब्याज तो छोड़िए, मूलधन मिलने की भी गुंजाइश नहीं होती है। इस लिस्ट में एक देश है, जिसका नाम है पोर्टो रिको।
- इसके अलावा मूडीज एक और रेटिंग जारी करती है और ये रेटिंग है आउटलुक रेटिंग। ये रेटिंग मूडीज का नजरिया बताती है कि मूडीज का उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचना है। यह रेटिंग भी चार तरह की होती है।
- मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग नहीं, आउटलुक रेटिंग घटाई है।
- **पॉजिटिव (POS)** : इसका मतलब यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है।
- **निगेटिव (NEG)** : इसका आशय यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब हालत में है। वो देश अपने लोन को चुकाने में नाकाम हो सकता है।

□ **स्टेबल (STA)** : इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत स्थिर है। वो न बहुत तेज गति से बढ़ रही है और न ही वो घट रही है। आसान भाषा में कहें तो वो देश लोन चुकाने में सक्षम है।

□ **डेवलपिंग (DEV)** : इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ रही है। यह किसी देश के लिए अच्छी स्थिति है। डेवलपिंग टैग वाले देशों पर निवेशकों की नजर रहती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में जी.डी.पी. के लिए बाहरी ऋण सिर्फ 20% है।
2. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के क्रेडिट रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से घटाकर सकारात्मक कर दिया है।
3. मूडीज के अनुसार, सरकार जी.डी.पी. के 3.3% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य के अभाव का सामना करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements regarding current Indian economy-

1. External debt for G.D.P. in Indian economy holds 20% share only.
2. Credit rating scenario of India has been improved from stable to positive by world rating agency 'Moodies'
3. According to moodies, government will face lack of target of GDP's 3.3% Fiscal deficit.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था के किन प्रमुख संकेतकों में सुधार न दिखाई पड़ने से रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को कम किया है? सरकार और वित्तीय नियामकों को इस दिशा में सुधार करने हेतु कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

Which were the indicators of Indian Economy with no improvement led rating agency moodies reduce india's rating? What steps should be taken by the government and fiscal regulators to make improvement in this direction? (250 words)

नोट : 9 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।